महाराष्ट्र राज्य और अन्य

बनाम

समस्त श्रमिक संघ, सांगली एवं अन्य।

(2006 की सिविल अपील संख्या 2565)

21 अक्टूबर, 2013

एच.एल. गोखले और रंजन गोगोई, जे.जे.

श्रम कानूनः

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-एस.एस. 25एफएफ, 25एफ और 25एन-कामगारों की सेवाओं की समाप्ति-उपक्रमों के स्थानांतरण के कारण-श्रम न्यायालय ने धारा 25एफ के तहत कामगारों को छंटनी मुआवजे का हकदार माना-उच्च न्यायालय ने माना कि मामला धारा 25एन के उल्लंघन का था और वे बहाली के हकदार थे सेवा की निरंतरता और 25 प्रतिशत बकाया वेतन के साथ-माना गयाः न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, पूर्ण न्याय करने के लिए श्रमिकों को सेवानिवृत्ति लाभ के साथ 25 प्रतिशत बकाया वेतन के साथ सेवा की निरंतरता का हकदार माना-तथ्यों में इस स्थिति में उन्हें बहाल नहीं किया जा सकता-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 142.

राज्य सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत 256 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. कुछ कामगारों ने छंटनी मुआवजा स्वीकार कर लिया। 163 श्रमिकों ने श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिन्होंने निर्देश दिया कि कोई बहाली नहीं होगी, लेकिन श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ के अनुसार छंटनी मुआवजे के हकदार थे। इसके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका श्रम न्यायालय को यह कहते हुए अनुमति दी गई कि यह अधिनियम की धारा 25एन के उल्लंघन का मामला है, न कि केवल धारा 25एफ का। पंचाट को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि तीन महीने का नोटिस या उसके बदले में भुगतान नहीं दिया गया था और इसलिए कामगार सेवा की निरंतरता के साथ बहाली के हकदार थे। 25 प्रतिशत पिछला वेतन भी प्रदान किया गया। एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध रिट अपील को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया। इसलिए राज्य के साथ-साथ ट्रेड यूनियन द्वारा वर्तमान क्रॉस अपील भी की गई है।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए

माना कि:

1. संबंधित कर्मचारी 25 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं पर पंप ऑपरेटर और चैकीदार आदि के रूप में लगे हुए थे, जो पानी पंप करने की प्रक्रिया

को अंजाम दे रहे थे। पानी पंप करने की प्रक्रिया विशेष रूप से फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 2 (क) (2) के तहत ''विनिर्माण प्रक्रिया की परिभाषा के अंतर्गत आती है। इस प्रकार, संबंधित कामगार ''विनिर्माण प्रक्रिया में लगे हुए थे। एक बार यह स्थापित हो जाये इसका तात्पर्य यह है कि जिस उपक्रम में वे काम कर रहे थे, उसकी गतिविधि उक्त अधिनियम की धारा 2 (एम) के अर्थ के भीतर एक ''कारखाना थी। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 ए का स्पष्टीकरण (1), ''औद्योगिक प्रतिष्ठान'' की परिभाषा के अंतर्गत ''कारखानों को शामिल करता है, और इसलिए 1947 अधिनियम का अध्याय 5 ए। ''विनिर्माण प्रक्रिया पर लागू होता है. पानी पंप करना. इसलिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस उपक्रम में संबंधित श्रमिक कार्यरत थे, वह 1947 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवर किया गया था। {पैरा 19}

उड़ीसा राज्य बनाम वी.एस. दंदासी साहू 1988 (4) एससीसी 12 1988 (1) सप्ल. एससीआर 562-पर निर्भर।

बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा और अन्य 1978 (2) एससीसी 213: 1978 (3) एससीआर 207-संदर्भित।

2. हो सकता है कि सिंचाई विभाग की सारी गतिविधियाँ हस्तांतरित न हुई हों, लेकिन उसकी एक अलग इकाई, जिसमें 25 लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं, एक चीनी कारखाने को हस्तांतरित होने की बात आयी

है। ऐसे मामले में एकमात्र दावा जो स्थानांतरणकर्ता कंपनी के कर्मचारी वैध रूप से कर सकते हैं, वह पिछले नियोक्ता के खिलाफ मुआवजे का दावा है, क्योंकि उन्हें नए नियोक्ता के तहत समाहित नहीं किया जा रहा है। {पैरा 21}

अनाकापल्ले सहकारी कृषि और औद्योगिक सोसायटी लिमिटेड बनाम श्रमिक और अन्य एआईआर 1963 एससी 1489: 1963 सप्ल. एससीआर 730-पर निर्भर।

3. संबंधित श्रमिकों में से कई लगभग 10 वर्षों की अवधि के लिए लगे हुए थे। 1947 अधिनियम की धारा 25 एफएफ उपक्रम के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप श्रमिकों को उनकी छंटनी के कारण भुगतान किए जाने वाले मुआवजे पर विचार करती है। हालाँकि, छँटनी केवल तभी की जानी आवश्यक है यदि पिछला नियोक्ता अपनी किसी भी गतिविधि या प्रतिष्ठान में संबंधित श्रमिकों को जारी नहीं रख रहा है, या जब उन्हें नए नियोक्ता के तहत अवशोषित नहीं किया जा रहा है। ऐसा अवसर आने पर मौजूदा नियोक्ता के अधीन सेवा जारी रखना या नए नियोक्ता के अधीन पुनः नियुक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेवाओं की समाप्ति सामान्यतः अंतिम उपाय होना चाहिए। वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि राज्य सरकार ने इन श्रमिकों को सिंचाई विभाग की अन्य गतिविधियों में शामिल करने के लिए कोई प्रयास किया है, या चीनी कारखाने पर उन्हें

अवशोषित करने के लिए जोर दिया है। इसका कारण यह है कि लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को स्थानांतरित चीनी मिल द्वारा जारी रखा जाना था, और किसी भी स्थिति में सिंचाई विभाग के पास बहुत बड़ी संख्या में गतिविधियाँ हैं, जिनमें इन श्रमिकों को शामिल किया जा सकता था। जब राज्य सरकार तस्वीर में होती है, तो उम्मीद की जाती है कि वह निजी क्षेत्र के नियोक्ता द्वारा अक्सर दिखाए जाने वाले रवैये की तुलना में थोड़ा बेहतर रवैया दिखाएगी। यह संभव है कि, किसी भी स्थिति में, राज्य सरकार की अपनी आर्थिक मजबूरियाँ हो सकती हैं जो सेवाओं को समाप्त करने को उचित ठहराती हैं। लेकिन, या तो ऐसे अधिशेष श्रमिकों को समाहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, या किसी भी मामले में, बर्खास्तगी की आवश्यकता के लिए सरकार की कठिनाइयों, यदि कोई हो, को समझाया जाना चाहिए। {पैरा 22}

4. इस न्यायालय के पास उसके समक्ष लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उचित आदेश पारित करने का अधिकार हैः संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस अधिकार को पूर्ण न्याय करने के कर्तव्य के साथ भी पढ़ा जाना चाहिए। किसी दिए गए मामले में न्याय. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह स्वीकार करते हुए कि समाप्ति उपक्रम के हस्तांतरण के कारण हुई, श्रमिकों को दी जाने वाली राहत को कुछ हद तक 10 के

दूसरे समूह को दी गई राहत के समान बनाना होगा। कामगार इसे 1947 अधिनियम की धारा 25एफ के साथ पठित 25एफ के तहत सीमित राहत की कठोरता तक सीमित रखना उचित और उचित नहीं होगा। 30.6.1985 को अपनी सेवाएँ समाप्त होने से पहले, संबंधित श्रमिकों में से कई ने लगभग 10 वर्षों की सेवा की थी। चूँकि तब से इतने वर्ष बीत चुके हैं, उनमें से अधिकांश सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँच चुके होंगे। ऐसी परिस्थिति में बहाली का आदेश नहीं दिया जा सकता. हालाँकि, वे सेवा की निरंतरता के हकदार होंगे, और यद्यपि वे 1947 अधिनियम की धारा 17 बी के तहत अंतिम आहरित वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे अन्य 10 कामगारों के बराबर 25 प्रतिशत बैकवेज और सेवानिवृत्ति लाभ के हकदार होंगे। उनके मामले में 25 प्रतिशत बकाया वेतन का पुरस्कार पर्याप्त मुआवजा होगा। {पैरा 26 और 27}

भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संघ बनाम भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य 1996 (9) एससीसी 439: 1996 (3) सप्ल. एससीआर 605; एल परमेश्वरन बनाम मुख्य व्यक्तिगत अधिकारी और अन्य 2008 (3) एससीसी 649: 2008 (2) एससीआर 1015-पर भरोसा किया गया।

5. ट्रेड यूनियन का 100 प्रतिशत बैकवेज का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। संघ श्रमिकों के वर्तमान समूह के लिए 10 श्रमिकों के अन्य समूह के साथ समानता के आधार पर राहत का दावा कर रहा है

जिसे इस न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। उन कामगारों को केवल 25 प्रतिशत बकाया वेतन दिया गया है। ऐसा होने पर, श्रमिकों के वर्तमान समूह को अन्य 10 श्रमिकों को दिए गए वेतन से अधिक बकाया वेतन नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, अधिक बकाया वेतन देने के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता। {पैरा 28}

कर्नाटक एग्रो प्रोटीन्स लिमिटेड के कर्मचारी बनाम कर्नाटक एग्रो प्रोटीन्स लिमिटेड और अन्य 1992 एलएलजे 712; सेंट्रल इनलैंड वॉटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम द वर्कमेन एंड अनादर (1974) 4 एससीसी 696: 1975 (1) एससीआर 153; मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम राम लाल और अन्य 2005 (2) एससीसी 638: 2005 (1) एससीआर 790; अनूप शर्मा बनाम कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य प्रभाग नंबर 1, पानीपत (हरियाणा) 2010 (5) एससीसी 497; वारलू बनाम गंगोत्रीबाई और अन्य 1995 (सप्लीमेंट) 1 एससीसी 37; निर्मल जीत सिंह हूण बनाम इर्तिजा हुसैन और अन्य 2010 (14) एससीसी 564: 2010 (14) एससीआर 109; यूपी राज्य. बनाम जय बीर सिंह 2005 (5) एससीसी 1: 2005 (1) पूरक एससीआर 20-संदर्भित।

केस कानून संदर्भः-

1992 एलएलजे 712 पैरा 9 में संदर्भित

1975 (1) एससीआर 153 पैरा 9 को संदर्भित करता है

2005 (1) एससीआर 790 पैरा 14 को संदर्भित किया गया

2010 (5) सेकंड 497 पैरा 15 को संदर्भित करता है

1995 (अनुपूरक) 1 सेकंड 37 पैरा 16 को संदर्भित किया गया

2010 (14) एससीआर 109 पैरा 17 को संदर्भित करता है

2005 (1) पूरक। एससीआर 20 पैरा 18 को संदर्भित करता है

1988 (1) पूरक। एससीआर 562 पैरा 20 पर निर्भर था

1978 (3) एससीआर 207 पैरा 20 को संदर्भित करता है

1963 सप्ल. एससीआर 730 पैरा 21 पर निर्भर था

1996 (3) सुपरऋप्ल. एससीआर 605 पैरा 26 पर निर्भर था

2008 (1) एससीआर 1015 पैरा 26 पर निर्भर था

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2565/2006.

डब्ल्यू.पी. संख्या 2699/1933 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के लेटर पेटेंट अपील संख्या 92/2005 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 12.09.2005 और 14.09.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत

मय

सीए 2006 की संख्या 2566

अपीलकर्ताओं के लिए माधवी दीवान, संजय वी. खरदे (आशा गोपालन नायर के लिए)

उत्तरदाताओं के लिए विनय नवरे, केशव रंजन, सत्यजीत कुमार, आभा आर शर्मा।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एचएल गोखले जे.

1. 2006 की सिविल अपील संख्या 2565 फैसले को चुनौती देने का प्रयास करती है और बॉम्बे हाई की डिविजन बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.9.2005 के लेटर पेटेंट अपील संख्या 184 में न्यायालय, साथ ही निर्णय और उस उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा रिट में पारित आदेश दिनांक 14.9.2004/1993 की याचिका संख्या 2699, जहां से उक्त पत्र पेटेंट अपील उत्पन्न हुई।

उक्त रिट याचिका को चुनौती देने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई थी श्रम न्यायालय, सांगली द्वारा एक समूह में पुरस्कार दिनांक 21.5.1992 प्रदान किया गया औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में आईडी अधिनियम) के तहत संदर्भ।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त द्वारा उक्त रिट याचिका को अनुमति दे दी थी। संदर्भित आदेश, और डिवीजन बेंच ने उक्त निर्णय अबाधित छोड़ दिया था।

2. सचिव सिंचाई के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य विभाग, और कार्यकारी अभियंता सिंचाई विभाग, सांगली हैं। यहां अपीलकर्ता, जबकि सर्व श्रमिक संघ, सांगली, एक ट्रेड यूनियन है। संबंधित कामगारों का प्रतिनिधित्व करना, और संबंधित कामगारों में से दो का प्रतिनिधित्व करना। औद्योगिक प्रतिष्ठान इस अपील के प्रतिवादी हैं।

तथ्य इस अपील के पीछे निम्नानुसार हैः-

3. महाराष्ट्र सरकार ने दिसंबर 1973 में सिंचाई विकास निगम महाराष्ट्र लिमिटेड नामक एक निगम की स्थापना की। यह निगम महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम था। इसने किसानों को मुफ्त सेवाएं प्रदान करने के लिए 25 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं स्थापित कीं। निगम की स्थापना वर्ष 1972 में राज्य को प्रभावित करने वाले भयानक सूखे के बाद की गई थी। उक्त निगम की सिंचाई योजनाओं पर काम करने के लिए लगभग 256 श्रमिकों को नियुक्त किया गया था। यद्यपि यह दावा किया गया था कि कामगार आकस्मिक और अस्थायी थे, तथ्य यह है कि उनमें से कई ने लगभग 10 वर्षों की सेवा की थी जब उन्हें 15.5.1985 को अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा समाप्ति के नोटिस दिए गए थे। नोटिस में उनकी सेवाओं को

30.6.1985 से समाप्त करने की मांग की गई, और उन्हें सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के मुआवजे की पेशकश की गई। छंटनी इसलिए की जा रही थी क्योंकि अपीलकर्ताओं के अनुसार लिफ्ट सिंचाई योजनाएं, जिस पर ये कामगार काम कर रहे थे, को एक चीनी कारखाने वसंतदादा शेतकारी सहकारी साखर कारखाना, सांगली में स्थानांतरित किया जा रहा था।

4. इसमें कोई विवाद नहीं है कि कुछ कामगारों ने छंटनी मुआवजा स्वीकार कर लिया, हालांकि उनमें से बड़ी संख्या ने ऐसा नहीं किया। उनमें से कुछ 163 ने पहले प्रतिवादी ट्रेड यूनियन के माध्यम से 1985 की रिट याचिका संख्या 2376 दायर की, उपरोक्त निगम और अपीलकर्ताओं के खिलाफ, उपक्रम के हस्तांतरण को रोकने की मांग की। याचिका को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था और इसलिए, 1986 की एसएलपी संख्या 1386 होने के कारण इस न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी गई थी। अपीलकर्ताओं ने उक्त याचिका का बचाव करते हुए कहा कि संबंधित कर्मचारी निगम के कर्मचारी नहीं थे, लेकिन राज्य के कर्मचारी थे. इसलिए, इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11.11.1986 द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए उक्त एसएलपी को खारिज कर दियाः

> "महाराष्ट्र राज्य के कार्यकारी अभियंता के जवाबी हलफनामे में दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए कि

याचिकाकर्ता राज्य के कर्मचारी थे, निगम के नहीं, हमें नहीं लगता कि इस याचिका में निगम के खिलाफ मांगी गई राहत कैसे दी जा सकती है। यदि याचिकाकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ कोई राहत पाना चाहते हैं और यदि ऐसी राहत स्वीकार्य है, तो याचिकाकर्ता इस मामले में उचित कानूनी उपाय खोजने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए, एसएलपी का तदनुसार निपटारा किया जाता है।"

5. इससे श्रमिकों को आईडी अधिनियम के तहत औद्योगिक विवाद का संदर्भ लेने के लिए प्रेरित किया गया । इन सन्दर्भों को आईडी नंबर 27 से 40, 42 से 70, 72 से 99/97, 1/88 से 35, 54, 63, 65, 72 से 92, 106 से 118/88, 17 से 29/89, 37, 38, 40 से 44/89 के रूप में 163 आवेदकों को कवर करते हुए क्रमांकित किया गया।

6. इन संदर्भों में, श्रमिकों की ओर से यह तर्क दिया गया था कि उनकी छंटनी अवैध थी, क्योंकि आईडी अधिनियम के तहत आवश्यक पर्याप्त वैधानिक नोटिस की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया था। प्रथमदृष्ट्या, नोटिस देने में कुछ दिनों की कमी थी। विद्वान श्रम न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि नोटिस 25.6.1985 को जारी किए गए थे, और सेवाएं 30.6.1985 से समाप्त कर दी गई थीं। श्रमिकों ने तर्क दिया कि जिन लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में वे काम कर रहे थे, वे वास्तव में

औद्योगिक प्रतिष्ठान थे, और चूँकि उनमें 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत थे, आईडी अधिनियम की धारा 25 एन के प्रावधान (जिसके लिए समाप्ति से तीन महीने पहले अग्रिम सूचना की आवश्यकता होती है) लागू थी, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया था। श्रम न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने उस दलील पर विचार नहीं किया, लेकिन यह माना कि किसी भी मामले में आईडी अधिनियम की धारा 25 एफ का उल्लंघन हुआ था, यहाँ तक कि एक महीने का नोटिस भी नहीं दिया गया था और इसलिए समाप्ति अवैध थी।

7. श्रम न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता क्रमांक 2 द्वारा दायर लिखित बयान में, पैराग्राफ 3 में कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा अपने खर्च पर विभिन्न योजनाएं संचालित की गईं। पैराग्राफ 4 में यह तर्क दिया गया कि संबंधित श्रमिक सिंचाई विभाग के कर्मचारी थे। इसके पैराग्राफ 14 में, यह कहा गया था कि

> ''समाप्ति उत्पीड़न के माध्यम से नहीं है, बल्कि चूंकि सिंचाई योजना शेतकारी सहकारी साखर कारखाना, सांगली को हस्तांतरित कर दी गई है, इसलिए कर्मचारी बिना किसी काम के सेवाओं में बने रहने के हकदार नहीं हैं।''

8. लिखित बयान में आईडी अधिनियम की धारा 25 एफएफ का कोई विशेष संदर्भ नहीं था जो उपक्रमों के हस्तांतरण से संबंधित है। विद्वान

न्यायाधीश के निर्णय में भी उक्त धारा का कोई संदर्भ नहीं था। हालाँकि, हम यह नोट कर सकते हैं कि विद्वान न्यायाधीश ने अपने आदेश के पैराग्राफ 8 में अपीलकर्ताओं की इस दलील को निम्नलिखित शब्दों में नोट किया हैः -

> "8........हालाँकि, वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि वे सभी योजनाए जहाँ दूसरे पक्ष के कर्मचारी काम कर रहे थे, राज्य सरकार द्वारा वसंतदादा शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, सांगली को बेच दी गई थीं और उक्त कारण से उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई। ऐसे में यह स्पष्ट है कि उन योजनाओं को चीनी उद्योग को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसलिए, उन योजनाओं पर प्रथम पक्ष नियोक्ता का कोई नियंत्रण नहीं है।"

9. हालाँकि, विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित कर्मचारी अस्थायी आधार पर नियोजित थे। यह ध्यान देने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने कर्नाटक एग्रो प्रोटीन्स लिमिटेड के कामगारों बनाम कर्नाटक एग्रो प्रोटीन्स लिमिटेड और अन्य के बीच कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। धारा 25 एफ और 25 एफएफ के आवेदन पर 1992 एलएलजे पृष्ठ 712 में रिपोर्ट की गई और माना गया कि श्रमिक जो एकमात्र दावा कर सकते थे वह मुआवजे के लिए था। कर्नाटक उच्च

न्यायालय ने अनाकापल्ले सहकारी कृषि और औद्योगिक सोसायटी लिमिटेड बनाम कर्मकार और अन्य मामले में निर्धारित कानून का उल्लेख किया था और उसका पालन किया था। एआईआर 1963 एससी 1489 में रिपोर्ट की गई, और सेंट्रल इनलैंड वॉटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम द वर्कमेन और अन्य में इस अदालत के बाद के फैसले की भी रिपोर्ट (1974) 4 एससीसी 696 में इसी प्रभाव से की गई। इसलिए, श्रम न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई बहाली नहीं होगी, लेकिन श्रमिकों को आईडी अधिनियम की धारा 25 एफ के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। श्रम न्यायालय का निर्णय इस प्रकार हैः-

''पंचाट''

(1) दावा आंशिक रूप से स्वीकृत है।

(2) सभी कर्मचारी प्रथम पक्ष के साथ अपनी सेवा अवधि की गणना के बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफ के तहत छंटनी मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं। शेष दावा खारिज किया जाता है।

(3) हालाँकि, प्रथम पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि जब भी नई परियोजना के लिए कुछ अतिरिक्त काम शुरू किया जाए या काम उपलब्ध हो तो उन सभी कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए।

(4) यह सूचित किया गया है कि कुछ कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में उनके कानूनी उत्तराधिकारी मुआवजा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

(5) इस पुरस्कार के प्रकाशन की तारीख से एक महीने के भीतर पुरस्कार लागू किया जाएगा।

(6) लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

10. उस निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 का उपयोग करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष 1993 की रिट याचिका संख्या 2699 दायर की। मामले की सुनवाई करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार किया कि पानी पंप करने की प्रक्रिया जिसमें श्रमिकों को नियोजित किया गया था, फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 2 (क) के तहत एक ''विनिर्माण प्रक्रिया थी, और इसलिए, लिफ्ट सिंचाई योजनाएं उक्त अधिनियम की धारा 2(एम) के तहत परिभाषित एक'' ''
थे और इसलिए, एक ''औद्योगिक प्रतिष्ठान'' जिस पर आईडी अधिनियम लागू होता था।

11. विद्वान एकल न्यायाधीश ने तब माना कि चूंकि राज्य सरकार के अनुसार, श्रमिकों को सिंचाई विभाग द्वारा नियोजित किया गया था, यह

दलील कि उपक्रम के हस्तांतरण के कारण उनकी सेवाओं को समाप्त करने की आवश्यकता थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह इस स्तर पर था क्योंकि लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के हस्तांतरण के बाद भी सिंचाई विभाग की अन्य गतिविधियाँ जारी रहीं, संबंधित श्रमिकों को निश्चित रूप से सिंचाई विभाग की अन्य गतिविधियों में शामिल किया जा सकता था।

12. विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि धारा 25एफएफ को लागू करने वाली याचिका को उच्च न्यायालय में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि स्थानांतरण तथ्यों और कानून का एक मिश्रित प्रश्न था। विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, यह धारा 25एन के उल्लंघन का मामला था, न कि केवल आई डी अधिनियम की 25एफ का। धारा 25एन औद्योगिक प्रतिष्ठानों से श्रमिकों की छंटनी के लिए पूर्ववर्ती शर्तें बताती है, जहां 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, और इसकी उपधारा (1)(ए) में छंटनी की स्थिति में तीन महीने का नोटिस या उसके बदले भुगतान का प्रावधान है। इसलिए, विद्वान न्यायाधीश ने पंचाट को रद्द कर दिया, क्योंकि तीन महीने की अग्रिम सूचना या वेतन नहीं दिया गया था, और माना कि कामगार सेवा की निरंतरता के साथ बहाली के हकदार थे। विद्वान न्यायाधीश ने कामगारों को 25 प्रतिशत बकाया वेतन प्रदान किया। निर्णय के पैराग्राफ 11 से 14 में निहित विद्वान न्यायाधीश के आदेश का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार हैः -

“11. श्रम न्यायालय, सांगली द्वारा पारित 21 मई 1992 के फैसले को रद्द कर दिया गया है। संदर्भ में संबंधित कर्मचारी सेवा की निरंतरता और 25 प्रतिशत बकाया वेतन के साथ बहाली के हकदार हैं। रोजगार के इच्छुक सभी कामगारों को इस आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद प्रतिवादी उन्हें एक माह के अंदर सेवा की निरंतरता के साथ बहाल कर रोजगार देंगे. कर्मियों को उनकी सेवा में बहाली के तीन महीने के भीतर 25 प्रतिशत की गणना करके बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा।

12. कुछ श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार के अन्य विभागों में समाहित कर लिया गया है या कहीं और रोजगार प्राप्त कर लिया है। इन कामगारों को आज से छह महीने के भीतर रोजगार प्राप्त करने की तिथि तक 25 प्रतिशत बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा।

13. इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान कुछ कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच चुके हैं। उन्हें आज से तीन महीने के भीतर सेवानिवृत्ति की आयु

प्राप्त करने की तारीख तक 25 प्रतिशत की गणना की गई बकाया मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

14. मुझे सूचित किया गया है कि अदालत में कार्यवाही लंबित रहने के दौरान कुछ श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। प्रतिवादी इन श्रमिकों के वारिसों को आज से तीन महीने के भीतर इन श्रमिकों की मृत्यु की तारीख तक की बकाया मजदूरी का 25 प्रतिशत भुगतान करेंगे।''

13. यह वह आदेश है जिसे लेटर्स पेटेंट अपील में चुनौती दी गई थी। हालाँकि, डिवीजन बेंच ने यह विचार किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर रिट याचिका पर पारित आदेश के खिलाफ एक लेटर्स पेटेंट अपील उपलब्ध नहीं थी, और इसलिए उक्त लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया। खंडपीठ और विद्वान एकल न्यायाधीश के इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील दायर की गई है। इस मामले में 8.5.2006 को अनुमति दी गई थी, और आईडी अधिनियम, 1947 की धारा 17बी के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। अपील तब से लंबित है, और जैसा कि दोनों पक्षों द्वारा दायर किया गया है। जब अपील अंतिम सुनवाई के लिए पहुंची, तो सुश्री माधवी दीवान, विद्वान वकील अपीलकर्ताओं की ओर से

उपस्थित हुईं, और श्री विनय नवारे, विद्वान वकील उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित हुए।

अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँः-

14. अपीलकर्ताओं की विद्वान वकील सुश्री माधवी दीवान की मुख्य दलील यह है कि यह एक उपक्रम के हस्तांतरण का मामला है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लिखित बयान के पैराग्राफ 14 में यही दलील दी गई थी, और श्रम न्यायालय के फैसले में भी यह प्रतिबिंबित हुआ था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य को नजरअंदाज करके स्पष्ट रूप से गलती की थी। सुश्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि वास्तव में यह स्वयं उत्तरदाताओं का भी मामला था कि उनकी सेवाओं की छंटनी उपक्रम के हस्तांतरण के कारण हुई थी। उनका कहना है कि लिफ्ट सिंचाई योजनाएं एक उपक्रम थीं और उपक्रम के प्रबंधन का स्वामित्व हस्तांतरित किया जा रहा था, और यह प्रासंगिक नहीं था कि सिंचाई विभाग निगम का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जा रहा था। इसलिए, उनके प्रस्तुतीकरण में यह धारा 25 एफएफ है जो वर्तमान मामले पर लागू होती है, और न ही धारा 25 एन और न ही धारा 25 एफ । इसके अलावा, धारा 25 एफ केवल मुआवजे के एक उपाय के रूप में लागू होगी जो प्रदान किया जाना है, और अनाकापल्ले सोसाइटी के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की संविधान पीठ

द्वारा निर्धारित के अलावा और कुछ नहीं होगा। उस मामले में इस न्यायालय ने पैराग्राफ 16 में निम्नानुसार टिप्पणी की हैः-

"16. सॉलिसिटर-जनरल का तर्क है कि वर्तमान अपील में प्रश्न अब औद्योगिक न्यायनिर्णयन के सामान्य सिद्धांतों के प्रकाश में नहीं, बल्कि धारा 25 एफएफ के विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है। उनका तर्क है, और हम सही सोचते हैं, कि खंड का पहला भाग यह मानता है कि किसी उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन के हस्तांतरण पर, उक्त उपक्रम में लगे श्रमिकों का रोजगार समाप्त हो जाता है, और यह भुगतान का प्रावधान करता है उक्त कर्मचारियों को उनकी सेवाओं की कथित समाप्ति के कारण मुआवजा, बशर्ते, वे अनुभाग द्वारा निर्धारित सेवा की लंबाई के परीक्षण को पूरा करते हों। उक्त भाग यह भी बताता है कि किस प्रकार और किस सीमा तक उक्त मुआवजे का भुगतान किया जाना है। कर्मचारी धारा के प्रावधानों के अनुसार नोटिस और मुआवजे के हकदार होंगे। 25-एफ, अनुभाग कहता है, जैसे कि उनकी छंटनी कर दी गई हो। अंतिम खंड स्पष्ट रूप से इस तथ्य को सामने लाता है कि कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति कानूनन छंटनी नहीं है

और यह हरिप्रसाद के मामले में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप है {1957} 1 एससीआर 121: एआईआर 1957 एससी 121। विधानमंडल, हालाँकि, यह प्रदान करना चाहता था कि हालाँकि इस तरह की समाप्ति तकनीकी रूप से तथाकथित छंटनी नहीं हो सकती है, जैसा कि इस न्यायालय ने निर्णय लिया है, फिर भी जिन कर्मचारियों की सेवाएँ उपक्रम के हस्तांतरण द्वारा समाप्त की गई हैं, वे मुआवजे के हकदार होने चाहिए, और इसलिए, धारा 25-एफएफ में प्रावधान है कि ऐसी समाप्ति पर उन्हें मुआवजे का भुगतान किया जाएगा जैसे कि उक्त समाप्ति छंटनी थी। शब्द ''मानो धारा 2(ओओ) द्वारा परिभाषित छंटनी के बीच कानूनी अंतर को उजागर करते हैं। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी और स्थानांतरण के परिणामस्वरूप सेवाओं की समाप्ति जिसके साथ यह संबंधित है। दूसरे शब्दों में, धारा यह बताती है कि यद्यपि स्थानांतरण पर सेवाओं की समाप्ति छंटनी नहीं हो सकती है, संबंधित कर्मचारी मुआवजे के हकदार हैं जैसे कि उक्त समाप्ति छंटनी थी। यह प्रावधान ऐसे कामगारों को देय मुआवजे की राशि की गणना करने के उद्देश्य से किया गया

> है; मुआवजे के माप को फिर से प्रदान करने के बजाय, एस। 25 एफएफ एस का संदर्भ देता है। 25-एफ उस सीमित उद्देश्य के लिए, और इसलिए, सभी मामलों में जिसके लिए एस. 25 एफएफ लागू होता है, एकमात्र दावा जो स्थानांतरित कंपनी के कर्मचारी वैध रूप से कर सकते हैं वह अपने नियोक्ताओं के खिलाफ मुआवजे का दावा है। उक्त संस्था के अंतरणकर्ता के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है।''

अनाकापल्ले (सुप्रा) में इस फैसले का उसके बाद लगातार पालन किया गया है, जिसमें इस न्यायालय का हालिया फैसला मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम राम लाल और अन्य, 2005 (2) एससीसी 638 भी शामिल किया गया है।

उत्तरदाताओं की ओर से उत्तरः-

15. जहां तक उत्तरदाताओं का सवाल है, उन्होंने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि धारा 25 एफएफ का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है, और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही ही माना है कि यह एक ऐसा मामला है जो धारा 25 एन के अंतर्गत आता है । यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 25 एन(1)(ए) के मद्देनजर, श्रमिकों को तीन महीने की पूर्व सूचना या नोटिस वेतन दिया जाना था। ऐसा नहीं किया गया है, और उपयुक्त सरकार की 25 एन(1)(बी) के तहत पूर्व अनुमति नहीं मांगी

गई है, छंटनी को 25एन की उप-धारा (7) के तहत अवैध माना जाएगा। श्रम न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने किसी भी मामले में माना था कि यह धारा 25एफ के उल्लंघन का मामला था, और उच्च न्यायालय ने माना था कि यह धारा 25एन के उल्लंघन का मामला था। इनमें से किसी भी निष्कर्ष ने पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाली को उचित ठहराया। इस संबंध में 2010 (5) एससीसी 497 में रिपोर्ट किए गए अनूप शर्मा बनाम कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाग नंबर 1, पानीपत (हरियाणा) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया था।

16. हालाँकि, इससे भी अधिक, उत्तरदाताओं ने बताया है कि समान लिफ्ट सिंचाई योजनाओं पर काम करने वाले 10 श्रमिकों (पांडुरंग विष्णु सैंडेज और 9 अन्य) के एक अन्य समूह ने बाद में श्रम न्यायालय में अलग-अलग रेंफरेंस के साथ संदर्भ दायर किए थे। (आईडीए) 1991 की संख्या 37 से 45 और 1992 की 1, और श्रम न्यायालय ने 30.12.1996 को एक पंचाट दिया, कि वे 10 कामगार 25 प्रतिशत बकाया वेतन के साथ बहाली के हकदार थे। उस फैसले को महाराष्ट्र राज्य द्वारा 1997 की रिट याचिका संख्या 2729 दायर करके चुनौती दी गई थी। वर्तमान मामले में 1993 की रिट याचिका संख्या 2699 के फैसले पर भरोसा करते हुए, उक्त रिट याचिका को बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं द्वारा 2006 की एसएलपी (सी) संख्या

773 को प्राथमिकता देते हुए एक अपील दायर की गई थी। इस माननीय न्यायालय ने देरी के आधार पर उक्त एसएलपी को खारिज कर दिया। 2006 की संख्या 379 वाली एक समीक्षा याचिका (सिविल) दायर की गई थी। जिसे 26.9.2006 को पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद 2007 की एक उपचारात्मक याचिका संख्या 164 दायर की गई। वह भी 21.2.2008 को खारिज हो गया। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता 10 श्रमिकों के उपरोक्त मामले में निर्णय से बंधे हैं, और किसी भी मामले में इस न्यायालय को वर्तमान अपील की अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे उन श्रमिकों के मामले में एक अलग परिणाम होगा जो समान हैं स्थित। उत्तरदाताओं ने वारलू बनाम गंगोत्रीबाई और अन्य के मामले में इस न्यायालय के एक आदेश पर भरोसा किया । 1995 में रिपोर्ट की गई (सप्लीमेंट) 1 एससीसी 37। यह अपीलकर्ता के किरायेदारी अधिकारों से संबंधित मामला था, तीन सर्वेक्षण संख्याओं में फैली भूमि के संबंध में, जो प्रतिवादी संख्या 1 की थी। उनके द्वारा दायर राजस्व कार्यवाही से उत्पन्न तीन रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गईं। उनमें से दो एसएलपी को कालातीत पाया गया और इसलिए खारिज कर दिया गया। जहां तकतीसरी एसएलपी का सवाल है, इस न्यायालय ने इस पर विचार करने से केवल इस कारण से इंकार कर दिया कि इस तरह के किसी भी हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप एक ही भूमि

में किरायेदारी अधिकारों के संबंध में विरोधाभासी आदेश दिए जाएंगे। इसलिए, प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री नवारे द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ताओं को रिकॉर्ड द्वारा रोक के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

17. इस तर्क के समर्थन में कि अन्य 10 श्रमिकों के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का वर्तमान मामले में पालन किया जाना चाहिए, निर्मल जीत सिंह हून बनाम इर्तिजा हुसैन और अन्य, 2010 (14) एससीसी 564 के मामले में एक निर्णय के पैराग्राफ 21 पर भरोसा किया गया था। किरायेदार को बेदखल करने का निर्देश देने वाले उस मामले में दिए गए फैसले को पहले की एसएलपी में पहले ही बरकरार रखा जा चुका था, जिसमें याचिकाकर्ता भी एक पक्ष था। उनकी ओर से दूसरी याचिका पर विचार करना, इस न्यायालय के पहले के आदेश की समीक्षा करने के समान होगा। इस न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि "कानून एक ही विषय के संबंध में एक ही मामले में दो विरोधाभासी और असंगत आदेशों की अनुमति नहीं देता है"। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि अन्य 10 श्रमिकों के मामले में श्रम न्यायालय के आदेश को अंतिम रूप दे दिया गया है, और अपीलकर्ताओं को वर्तमान मामले में एक अलग स्थिति लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब दोनों मामलों में श्रमिकों की स्थिति समान थी।

18. अपीलकर्ताओं ने कहा था कि सिंचाई विभाग कोई उद्योग नहीं है। उस संबंध में, श्रमिकों की ओर से यह बताया गया था कि बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा और अन्य 1978 (2) एससीसी 213 में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर यह सबमिशन उठाने में बहुत देर हो चुकी है । इसके विपरीत, अपीलकर्ताओं के वकील ने बताया कि बैंगलोर जल आपूर्ति (सुप्रा) में निर्णय पारित आदेश के मद्देनजर इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ के समक्ष पुनर्विचार के लिए लंबित है। यूपी राज्य बनाम जय बीर सिंह मामले में संविधान पीठ ने 2005 (5) एससीसी 1 में रिपोर्ट दी थी। हालांकि, उत्तरदाताओं ने कहा कि इस बीच बैंगलोर जल आपूर्ति (सुप्रा) में फैसले का तब तक पालन करना होगा जब तक कि इसे खारिज नहीं किया जाता है। चूँकि उसमें दिया गया प्रस्ताव अब भी कायम है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर भरोसा किया जाता है, उड़ीसा राज्य बनाम दंडसी साहू में मध्यस्थता से संबंधित मामले में 1988 (4) एससीसी 12 में रिपोर्ट की गई थी। उस मामले में इस न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के विवेक का प्रयोग करते हुए, किसी पक्ष को बड़ी पीठ का निर्णय प्राप्त होने तक पुराने और बासी विवादों के निर्णय को आगे बढ़ाने या परेशान करने की अनुमति देना उचित नहीं होगा।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचारः-

19. (1) सबसे पहले, हमें ध्यान देना चाहिए कि संबंधित कर्मचारी 25 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं पर पंप ऑपरेटर और चैकीदार आदि के रूप में लगे हुए थे, जो पानी पंप करने की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे थे। पानी पंप करने की प्रक्रिया विशेष रूप से फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 2 (के)(पप) के तहत'' '' प्रकार, संबंधित श्रमिक ''विनिर्माण प्रक्रिया में लगे हुए थे। एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद, यह इस प्रकार है कि जिस उपक्रम में वे काम कर रहे थे, उसकी गतिविधि उक्त अधिनियम की धारा 2 (एम) के अर्थ के तहत एक ''कारखाना थी।

(2) आईडी अधिनियम, 1947 की धारा 25ए का स्पष्टीकरण (प), ''औद्योगिक प्रतिष्ठान'' की परिभाषा के भीतर ''कारखानों को शामिल करता है, और इसलिए आईडी अधिनियम, 1947 का अध्याय 5ए पंपिंग पानी की ''विनिर्माण प्रक्रिया पर लागू होता है। इसलिए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जिस उपक्रम में संबंधित श्रमिक कार्यरत थे, वह आईडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवर किया गया था ।

20. हालाँकि, अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि उक्त उपक्रम प्रथम अपीलकर्ता के सिंचाई विभाग द्वारा चलाया जा रहा था, और सिंचाई विभाग की गतिविधियों को इसकी परिभाषा के भीतर ''उद्योग'' नहीं माना जा सकता है। आईडी अधिनियम की धारा 2(जे) के तहत अवधारणा।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (सुप्रा) में ''उद्योग'' की अवधारणा की व्यापक व्याख्या पर पुनर्विचार इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ के समक्ष लंबित है। हालाँकि, अभी हमें इस क्षेत्र में वर्तमान में मौजूद कानून की व्याख्या का पालन ऊपर उल्लिखित उड़ीसा राज्य बनाम दंडसी साहू (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुसार करना होगा। वर्तमान लंबित औद्योगिक विवाद का निर्धारण तब तक अनिर्णीत नहीं रखा जा सकता जब तक कि वृहद पीठ का निर्णय प्राप्त न हो जाये।

21. यह कहते हुए कि, हालांकि, बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले पर अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति पर गौर किया जाना आवश्यक है। अपीलकर्ताओं ने एक उपक्रम का हस्तांतरण किया था जिसके परिणामस्वरूप संबंधित श्रमिकों की सेवाएं समाप्त हो गईं, और यह सीधे तौर पर छंटनी का मामला नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया कि 25 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं अपने आप में एक उपक्रम हैं। हो सकता है कि सिंचाई विभाग की सारी गतिविधियाँ हस्तांतरित न हुई हों, लेकिन उसकी एक अलग इकाई, जिसमें ये 25 लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं, एक चीनी कारखाने को हस्तांतरित होने की बात आयी है। जैसा कि अनाकापल्ले सोसाइटी के मामले (सुप्रा) में माना गया है, ऐसे मामले में एकमात्र दावा जो स्थानांतरणकर्ता कंपनी के

कर्मचारी वैध रूप से कर सकते हैं, वह पिछले नियोक्ता के खिलाफ मुआवजे का दावा है, क्योंकि उन्हें नए नियोक्ता के तहत अवशोषित नहीं किया जा रहा है।

22. यह कहने के बाद, हमें अपीलकर्ताओं के आचरण पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित कई कर्मचारी लगभग 10 वर्षों की अवधि से कार्यरत थे। धारा 25 एफएफ उपक्रम के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप श्रमिकों को उनकी छंटनी के कारण भुगतान किए जाने वाले मुआवजे पर विचार करती है। हालाँकि, छँटनी केवल तभी की जानी आवश्यक है यदि पिछला नियोक्ता अपनी किसी भी गतिविधि या प्रतिष्ठान में संबंधित श्रमिकों को जारी नहीं रख रहा है, या जब उन्हें नए नियोक्ता के तहत अवशोषित नहीं किया जा रहा है। ऐसा अवसर आने पर मौजूदा नियोक्ता के अधीन सेवा जारी रखना या नए नियोक्ता के अधीन पुनः नियुक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेवाओं की समाप्ति सामान्यतः अंतिम उपाय होना चाहिए। इस मामले में, प्रथम अपीलकर्ता-राज्य सरकार, ने इन श्रमिकों को सिंचाई विभाग की अन्य गतिविधियों में शामिल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है, या चीनी कारखाने पर उन्हें अवशोषित करने के लिए जोर दिया है। इसका कारण यह है कि लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को स्थानांतरित चीनी मिल द्वारा जारी रखा जाना था, और किसी भी स्थिति में सिंचाई विभाग के पास बहुत बड़ी संख्या में गतिविधियाँ हैं,

जिनमें इन श्रमिकों को शामिल किया जा सकता था। जब राज्य सरकार तस्वीर में होती है, तो हम उस रवैये की तुलना में थोड़ा बेहतर रवैये की उम्मीद करते हैं जो अक्सर निजी क्षेत्र के नियोक्ता द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह संभव है कि, किसी भी स्थिति में, राज्य सरकार की अपनी आर्थिक मजबूरियाँ हो सकती हैं जो सेवाओं को समाप्त करने को उचित ठहराती हैं। लेकिन, या तो ऐसे अधिशेष श्रमिकों को समाहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, या किसी भी मामले में, बर्खास्तगी की आवश्यकता के लिए सरकार की कठिनाइयों, यदि कोई हो, को समझाया जाना चाहिए। हमें रिकॉर्ड पर ऐसा कोई प्रयास या स्पष्टीकरण नहीं मिला।

23. यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि श्रम न्यायालय ने राज्य सरकार को इन श्रमिकों के अवशोषण पर विचार करने का निर्देश दिया था। उत्तरदाताओं ने यह रिकॉर्ड में रखा है कि सिंचाई विभाग में रोजगार के लिए एक बाद के विज्ञापन के अनुसरण में, पहले प्रतिवादी-संघ ने इन श्रमिकों को शामिल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा था, लेकिन सरकार ने संघ को सूचित करने के लिए नौकरशाही रवैया अपनाया कि नहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण ऐसा निर्णय लिया जा सका। एक कल्याणकारी राज्य से इस रवैये की अपेक्षा नहीं थी.

24. किसी भी मामले में, यह देखते हुए कि समान लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के 10 अन्य कामगारों से संबंधित एक अन्य याचिका खारिज

कर दी गई थी, और एसएलपी और क्यूरेटिव याचिकाएं भी खारिज कर दी गई थीं, इस न्यायालय के लिए यह विचार करने का प्रश्न उठता है कि यह एक मामला था। उपक्रम के हस्तांतरण के मामले में, प्रभावित कामगारों को राहत केवल धारा 25 एफ के तहत मुआवजे तक ही सीमित होनी चाहिए, जैसा कि एस 25 एफएफ द्वारा अपेक्षित है।

25. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने राजस्व कार्यवाही और किराया अधिनियम से उत्पन्न कुछ मामलों का उल्लेख किया है, जो दर्शाता है कि ऐसी स्थिति में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। ये 163 कामगार और अन्य 10 कामगार अर्थात। पांडुरंग विष्णु संदगे और अन्य लोग उन्हीं लिफ्ट सिंचाई योजनाओं पर काम कर रहे थे। उन 10 कर्मियों को 25 प्रतिशत बैकवेज के साथ बहाली का पुरस्कार भी मिला। उस फैसले को चुनौती देने वाली अपीलकर्ताओं की रिट याचिका को वर्तमान मामले में एकल न्यायाधीश के फैसले पर भरोसा करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। एसएलपी और उपचारात्मक याचिकाएं भी खारिज कर दी गईं, हालांकि अत्यधिक देरी के आधार पर। हालाँकि, तथ्य यह है कि जहाँ तक उन 10 कामगारों का सवाल है, उनके मामले में राहत का आदेश दिया गया है। 25 प्रतिशत बैकवेज के साथ बहाली और सेवा में निरंतरता को बरकरार रखा गया। इसलिए, एक सवाल उठता है-क्या सरकार को उन 10 श्रमिकों के मामले में सुस्त होना चाहिए, जहां उसे 25 प्रतिशत बैकवेज के साथ बहाली

का आदेश मिला था, अब उसे इस बात पर जोर देने की अनुमति दी जानी चाहिए कि जब इन 163 श्रमिकों की बात आती है, जो समान रूप से स्थित हैं, उन्हें तुलनीय राहत से वंचित किया जाएगा? और किसी भी मामले में, क्या इस न्यायालय को राहत के मामले में श्रमिकों के दो समूहों के साथ अलग-अलग व्यवहार करना चाहिए, केवल इसलिए कि उनमें से कुछ के खिलाफ एसएलपी देरी के कारण खारिज हो गई, जबकि अन्य के खिलाफ एसएलपी अंतिम बहस के लिए बची रही?

26. इस न्यायालय को अपने समक्ष लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उचित आदेश पारित करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस अधिकार को किसी दिए गए मामले में पूर्ण न्याय करने के कर्तव्य के साथ भी पढ़ा जाना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संघ बनाम भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य 1996 (9) एससीसी 439 में इस न्यायालय को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां इस न्यायालय के पहले के आदेश के बावजूद निर्दिष्ट श्रमिकों की बहाली में देरी हुई थी। इसका कारण औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में उनकी पहचान निर्धारित करने में लगभग 6 वर्षों की लंबी देरी थी। इसलिए, मामले में शामिल "मानवीय समस्या" को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने पूर्ण न्याय करने की दृष्टि से काम करने वालों की पहचान के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की, और

''सामान्य कमाई'' के 70 प्रतिशत की दर से बैकवेज के साथ बहाली का भी निर्देश दिया। श्रमिकों को उनकी बहाली तक पीस रेट पर रखा जाएगा। एल परमेश्वरन बनाम मुख्य व्यक्तिगत अधिकारी और अन्य 2008 (3) एससीसी 649 में रिपोर्ट की गई, अपीलकर्ता ने बहुत लंबे समय तक एक पूर्व-कैडर पद पर काम किया था, और उसे उसके मूल पद पर वापस भेज दिया गया था, हालांकि तुरंत नहीं जब पूर्व-कैडर कर्मचारियों को वापस भेजने का नीतिगत निर्णय लिया गया था। लंबे समय तक एक्स-कैडर पद पर काम करने से उस पद पर बने रहने या वेतन सुरक्षा का कोई अधिकार नहीं मिलता। हालाँकि, पूर्व-कैडर पद पर बिताए गए लंबे समय को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने उन्हें वेतन की सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 142 लागू किया।

27. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भी, यह स्वीकार करते हुए कि समाप्ति उपक्रम के हस्तांतरण के कारण हुई, श्रमिकों को दी जाने वाली राहत को कुछ हद तक दूसरे को दी गई राहत के समान बनाना होगा। 10 कामगारों का समूह. इसे आईडी अधिनियम की धारा 25 एफ के साथ पठित धारा 25 एफएफ के तहत सीमित राहत की कठोरता तक सीमित रखना उचित और उचित नहीं होगा। 30.6.1985 को अपनी सेवाएँ समाप्त होने से पहले, संबंधित श्रमिकों में से कई ने लगभग 10 वर्षों की सेवा की थी। चूँकि तब से इतने वर्ष बीत चुके हैं, उनमें से अधिकांश

सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँच चुके होंगे। ऐसी परिस्थिति में बहाली का आदेश नहीं दिया जा सकता. हालाँकि, वे सेवा की निरंतरता के हकदार होंगे, और यद्यपि वे आईडी अधिनियम, 1947 के एस 17 बी के तहत अंतिम आहरित वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे अन्य 10 कामगारों के बराबर 25 प्रतिशत बैकवेज और सेवानिवृत्ति लाभ के हकदार होंगे। उनके मामले में 25 प्रतिशत बकाया वेतन का पुरस्कार पर्याप्त मुआवजा होगा।

28. 2006 की सिविल अपील संख्या 2566 उपरोक्त ट्रेड यूनियन द्वारा दायर की गई है, जो 2006 की सिविल अपील संख्या 2565 में प्रतिवादी है, एकल न्यायाधीश और बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समान दो निर्णयों के खिलाफ। यूनियन कामगारों को केवल 25 प्रतिशत बकाया वेतन दिए जाने से व्यथित है, और 100 प्रतिशत बकाया वेतन का आदेश चाहती है, उनका तर्क है कि यदि छंटनी को कानून में बुरा माना जाता है, तो बकाया वेतन को 100 प्रतिशत से कम तक सीमित नहीं किया जा सकता है। बकाया श्री नवारे इस अपील के समर्थन में और सुश्री दीवान इसके विरोध में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि उपरोक्त तथ्यों के वर्णन से देखा जा सकता है, संघ श्रमिकों के वर्तमान समूह के लिए 10 श्रमिकों के अन्य समूह के साथ समानता के आधार पर राहत का दावा कर रहा है। पांडुरंग विष्णु संदगे और अन्य, और वह समर्पण हमारे द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। उन कामगारों को केवल 25 प्रतिशत बकाया वेतन दिया गया है।

ऐसा होने पर, श्रमिकों के वर्तमान समूह को अन्य 10 श्रमिकों को दिए गए वेतन से अधिक बकाया वेतन नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, अधिक बकाया वेतन देने के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता।

29. इन परिस्थितियों में, हम 1993 की रिट याचिका संख्या 2699 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 14.9.2004 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के खिलाफ दो अपीलों का निपटारा करते हैं, जिसे डिवीजन द्वारा अबाधित छोड़ दिया गया है। खंडपीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित करते हुएः-

(1) वर्तमान मामले से संबंधित 163 श्रमिकों को तीन श्रेणियों में रखा जाएगा, यानी, (ए) जो पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच चुके हैं; (बी) जो अभी तक सेवानिवृत्ति की आयु तक नहीं पहुंचे हैं; और (सी) जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वे निम्नलिखित तरीके से राहत के हकदार होंगे।

(2) श्रेणी (ए) के श्रमिकों को लाभ उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक, श्रेणी (बी) के लिए इस निर्णय की तारीख तक, और श्रेणी (सी) के लिए लाभ श्रमिक की समाप्ति की तारीख तक होगा।

(3) तीनों श्रेणियों के कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तारीख तक, या इस फैसले की तारीख तक, या उस तारीख तक, जिस दिन संबंधित कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, जैसा भी मामला हो, सेवा की निरंतरता के हकदार होंगे।

(4) सभी कामगार आईडी अधिनियम की धारा 17बी के तहत प्राप्त अंतिम वेतन के अलावा 25 प्रतिशत बैकवेज के हकदार होंगे। बकाया वेतन की गणना उपरोक्त खंड (3) में उल्लिखित तिथि तक की जाएगी।

(5) सभी कामगार उसी सेवानिवृत्ति लाभ के हकदार होंगे, यदि कोई हो (उनकी पात्रता के आधार पर), जैसा कि 10 कामगारों के अन्य समूह को दिया गया है। पांडुरंग विष्णु संदगे और अन्य।

(6) उपरोक्त सभी भुगतान इस फैसले की तारीख से तीन महीने के भीतर सीधे संबंधित श्रमिकों या उनके उत्तराधिकारियों को, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा।

(7) बहाली का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(8) इसके बाद, अपीलकर्ता सांगली के श्रम न्यायालय में एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगे, जिसकी एक प्रति इस न्यायालय की रजिस्ट्री को दी जाएगी।

(9) तदनुसार आदेश दें।

(10) रजिस्ट्री इस फैसले की एक प्रति श्रम न्यायालय, सांगली को भेजेगी।

30. दोनों अपीलें और सभी आई.ए.एस. उसमें स्थानांतरित की गई राशि को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के, ऊपर बताए अनुसार निपटाया जाएगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जीतेन्द्र सांवरिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।